Regarding condition of Adivasis in Santhal Parganas, Jharkhand

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदया, मैं पिछले 10 साल से या उससे अधिक समय से भी लगातार एक बात कह रहा हूं । मेरा संथाल परगना नामक इलाका है । इस सदन में सभी लोग अनुसूचित जाति की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं । सन् 1991 की जनगणना के अनुसार हमारे संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या 45 प्रतिशत थी । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की संख्या केवल और केवल 27 प्रतिशत है । अभी जो जनगणना शुरू होगी, तो मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि उनकी संख्या 21 या 22 प्रतिशत होगी ।

आदिवासी विलुप्त हो रहे हैं । उन आदिवासियों को विलुप्त करने में, जो वहां की राज्य सरकार है, वह ?आधार? का सहारा ले रही है । ?आधार? सिटिजनशिप का मामला नहीं है, बल्कि ?आधार? रेसिडेंट का प्रूफ है । उसके आधार पर वहां बांग्लादेशी घुसपैठिएं आ रहे हैं और वे वहां की लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं । वे जल, जंगल और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं । इस कारणवश एक ऐसा दिन आएगा, हमारे यहां वर्ष 2008 में जनगणना नहीं हुई थी । झारखंड में वर्ष 2008 में जनगणना इसलिए नहीं हुई थी, क्योंकि आदिवासियों की संख्या घटने के कारण अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) के लिए आरक्षित एक लोक सभा की सीट और छः विधान सभाओं की सीट्स समाप्त हो रही थीं ।

अभी जब नई जनगणना होगी, तो मुझे लगता है कि झारखंड में फिर से परिसीमन नहीं होगा, क्योंकि इस बार अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) के लिए आरक्षित लोक सभा की दो सीट्स और कम से कम विधान सभा की 12 सीट्स घटेंगी । यह पूरे देश के समक्ष एक समस्या है कि आदिवासियों की संख्या घट रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, जो हमारी बहू-बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वहां पर ?एनआरसी? लागू करिए और कोर्ट का जजमेंट भी यही कहता है । वहां से बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाइए, उनको नेस्तनाबूद करिए तथा हमारे झारखंड राज्य और संथाल परगना को बचाइए ।

13.00 hrs